

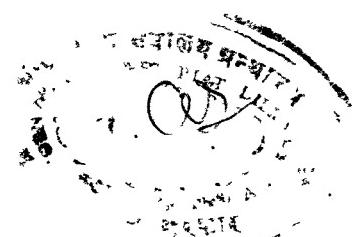


# भारत का गज़ीत The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—पांड 4  
PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 40]

नई दिल्ली, बृद्धवार, अक्टूबर 13, 1993/आश्विन 21, 1915

No. 40] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 1993/ASVINA 21, 1915

भारतीय खाद्य नियम

1

2

अधिकूचना स - 68  
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1993

सं. ई.पी.-39-3/83 खण्ड.- खाद्य नियम अधिनियम, 1964  
(1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करने  
हुए एवं बेन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय खाद्य नियम, भा.  
ख. नि (मृ. एवं से नि उपदान) विनियम, 1967 को सशोधन  
करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम जारी है -

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य नियम (पूर्ण एवं सेवा निवृत्त  
उपदान) (प्रथम सशोधन) विनियम, 1993 हैं जायेगे।
- (2) ये सशोधन दिनांक 1-1-1986 से चार यारे होंगे।

2 भारतीय खाद्य नियम (मृ. एवं से नि उपदान) विनियम, 1967  
के विनियम 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्निहित/जोड़े  
जायेंगे -

विनियम सं	जोड़े गये/नयोधित उप-विनियम
1	2
4 (2) परिस्थितिया	1 उपदान उन कर्मचारियों को देय नहीं होगा जिन्होंने पाच वर्षों की सेवा पूरी करने से पूर्व नौकरी में इस्तेवा दे दिया है।

2312 GI/93

(1)

(दिन रूप स्वेच्छा योग्यता के  
अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को  
इन्हीं ही जहाँ जायेगा),

2 कर्मचारी की जिसकी सेवाएं किसी  
पार्य, जनबुद्धिमत असाधारणी या  
नागरिकही के कारण नियोक्ता की  
संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुँचाने  
के कारण समाप्त कर दी गई हैं,  
तो उसकी उपदान क्षति या नुकसान  
के बराबर रूप से उठाने जाएगा;

3 निम्न नम्बरों को देय उपदान  
समूचा या प्रायिक रूप से उठाने किया  
जा याएगा है यदि

(क) निम्न नम्बरों की जिसकी सेवाएं  
यदि उमके बच्चों या अनुशासन-  
हानी की व्यवहार या कोई  
उत्तर दृष्टि नहीं होती। नन्हा हिस्सा के कारण  
समाप्त की जाए है,

या

1

2

(ए) ऐसे कर्मचारी को किसी गेवाएं यदि उसके ऐसे किसी कार्य जो नैतिक चरित्रहीनता का अपराध है, के कारण समाप्त की जा सकती है, अपार्टे कि ऐसा अपराध उसके द्वारा लोकरी के होरन किया गया हो।

## विनियम 4 (5) (क)

कर्मचारियों को उपदान का भुगतान किया जाता है, जहां मी इस विनियम के अनुमार देय है तथा प्रत्येक वर्ष में भुगतान मञ्चित्र कर्मचारियों को देय विधि में 30 दिन के अन्वर हो। यदि किसी कारणवश नियम द्वारा उपदान का भुगतान कर्मचारी को देय विधि से 30 दिन के अन्वर नहीं किया गया है तो मञ्चित्र कर्मचारी को साक्षात्रण व्याज का भुगतान ऐसी दर पर उपदान भुगतान की विधि तक किया जा येता जो लागती अवधि की अभावों के विपरीत भुगतान के लिये केवल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचित दर से अधिक नहीं हो। तथापि ऐसा व्याज कर्मचारी को देय नहीं होता यदि भुगतान में दरी कर्मचारी की गतिरौपि से हुई हो और नियम के इस आधार पर भुगतान में दरी के लिए विद्युत में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली ली हो।

## विनियम 4 (5) (ब्र)

उपदान भुगतान की दरों पर व्याज की मंजूरी के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी विनियम 4(5) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:—

वर्ग	कार्यालय	सक्षम प्राधिकारी
सभो वर्ग	मुख्यमंत्री, प्र.मं. / परि. का. प्रभाग	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक, १०वां संशोधन)
सभी वर्ग	आ.का. / क्षेत्र. का. सं.प्र. (व.का.) जिला कार्यालय	प्रांचलिक प्रश्नधरक

## विनियम 4(2) एवं 4 (5) (क) का विवरणात्मक ज्ञान

भा.खा.नि. (मू. एव सेनि. उपदान) विनियम, 1967 ई. पी.ई. उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ..... मांडल उपदान योजना के आधार पर है, जैसा कि डा.पा.ई. का.शा. सं 2 (29)/75-डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.) दिनांकित 23 जून 1988 में दिया हुआ है तथा भा.खा.नि. में दिनांक 1-1-1986 से प्रभावी अधिसूचना सं 53 दिमांकित 19 अप्रैल, 1990 के द्वारा विनियम 4(2), 4, 5 (1), 5(2) तथा 5(4) को संशोधित करके अपनाया गया। डी.पी.ई. ने का.शा. सं. 2(29) 75-डी.पी.ई. डब्ल्यू.सी. दिनांकित 27-5-1992, 11-6-1992 तथा 22-10-1992 के द्वारा दिनांक 1-1-1986 से भूतलवां प्रभाव के साथ अपने पूर्व का.शा. दिनांकित 23-6-1988 की प्रायः संशोधित किया।

ये संशोधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऐसे भुगतानों में दरी के कारण हुई कठिनाई से बचाने के लिए प्रावधक ये तथा उसीका के मामले के साथ-साथ अनुशासनहर्न नाम के घटहार आविष्कार के कारण बग्राहस्तानों के मामले में उपदान के भुगतान में अधिक प्रतिबंध लगाने को भी आवश्यक थे। जैसे कि ये सार्वजनिक उद्यमों का मरकारी निवेद्य है, यह नियम इन निर्देशों को भूतलवां प्रभाव के साथ लायू करने को आवश्यक है।

एन.एन. शर्मा, सचिव

भा.खा.नि. (मू. एव तथा सेवा निवृत्त उपदान) विनियम, 1967 में दूष पूर्ववर्ती संशोधनों की सूची

क्रम सं.	शीर्षक	राजपत्र का अंश	प्रकाशन की तिथि
1	2	3	4
1.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) विनियम, 1967	III छण्ड 4	9-9-67
2.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1976	"	26-10-76
3.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1978	"	3-11-78
4.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (तृतीय संशोधन) विनियम, 1978	"	16-11-78
5.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1981	"	25-7-81
6.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (पांचवां संशोधन) विनियम, 1982	"	28-8-82
7.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (छठवां संशोधन) विनियम, 1982	"	2-10-82
8.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (छवां संशोधन) विनियम, 1983	"	5-11-83
9.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (८वां संशोधन) विनियम, 1986	"	14-10-86
10.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (९वां संशोधन) विनियम, 1986	"	31-10-86
11.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (१०वां संशोधन) विनियम, 1988	"	19-4-88
12.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1990	"	19-4-90
13.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990	"	19-4-90
14.	भा.खा.नि. (मू. एव सेनि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1991	"	9-8-91

## THE FOOD CORPORATION OF INDIA

## NOTIFICATION NO. 68

New Delhi, the 12th October, 1993.

No. EP. 39-3/83 Pt.: In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to amend the FCI (DCRG) Regulations, 1967.

I. (1) These regulations shall be called the Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) (1st Amendment) Regulation, 1993.

(2) These amendments shall be deemed to have come into force w.e.f. 1-1-1993.

**II.** The following sub-regulations under Regulation 4 of the FCI (DCRG) Regulations, 1967 shall be inserted/added as under :

Regulation No.	Added/Amended sub-Regulations
4(2) Circumstances :	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Gratuity will not be payable to employees who resign from services before completing five years of service. (Voluntary retirement under a duly approved scheme would not constitute resignation);</li> <li>(ii) Gratuity of an employee whose services have been terminated for any act, wilful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of property belonging to the employer, shall be forfeited to the extent of damage or loss so caused;</li> <li>(iii) Gratuity payable to an employee may be wholly or partially forfeited: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) If the services of such employee have been terminated for his/her riotous or disorderly conduct or any other act of violence of his/her part, or</li> <li>(b) If the services of such employee have been terminated for any act which constitute an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of his employment.</li> </ul> </li> </ul>

#### REGULATION 4(5)(a)

The employees are to be paid gratuity immediately wherever due as per this regulation and in any case within 30 days from the date it becomes payable to the employees concerned. If for any reason the amount of gratuity payable to the employee is not paid by the Corporation within 30 days from the date on which gratuity had become payable simple interest at such rate not exceeding the rate notified by the Central Government from time to time for repayment of long term deposits, shall be paid to the employee concerned upto the date of payment of gratuity. However, no such interest shall become payable to the employee if the delay in the payment is due to the fault of the employee and the Corporation had obtained permission in writing from the concerned authority for the delayed payment on this ground.

#### REGULATION 4(5)(b)

The competent authority for the purpose of sanction of interest on the delayed payment of gratuity under Regulation 4(5)(a) would be the authorities indicated hereunder:

Category	Office	Authority Competent
All Categories	Hqrs. / CTI/PJD	Executive Director (Personnel)
All Categories	ZO/RO/JMs(PO)/ Distt. Offices	Zonal Manager

#### EXPLANATORY MEMORANDUM TO REGULATION 4(2) & 4(5)(a)

The FCI (DCRG) Regulations, 1967 are based on the Model Gratuity Scheme of the DPE, Ministry of Industry Government of India, as contained in O.M. No. 2(29)/75-DPE(WC) dated 23rd June, 1988 and adopted in the F.C.I. by amending Regulation 4(2), 4(4), 5(1), 5(2) and 5(4) vide notification No. 53 dated 19th April, 1990 effective from 1-1-1986. The DPE vide O.M. No. 2(29)/75-DPE WC dated 27-5-1992, 11-6-1992 and 22-10-92 has further amended their earlier O.M. dated 23-6-1988 with retrospective effect from 1-1-1986. These amendments were necessitated to avoid hardship to the retired employees due to delay in releasing such payments and also to bring more restrictions in payment of gratuity in case of resignation as well as termination due to disorderly conduct etc. As these are Government directives to PSEs, this Corporation is under an obligation to implement the same with retrospective effect.

S.N. SHARMA, Secy.

#### LIST OF PREVIOUS AMENDMENTS TO THE FCI (DCRG) REGULATIONS, 1967

Sl. No.	Title	Part of Gazette	Date of Publication
1	2	3	4
1.	FCI (DCRG), Regulations, 1967	III Section 4	9-9-1967
2.	FCI (DCRG), (1st Amendment) Regulations, 1976.	-do-	26-10-1976
3.	FCI (DCRG), (2nd Amendment) Regulations, 1978.	-do-	3-11-1978
4.	FCI (DCRG), (3rd Amendment) Regulations, 1978.	-do-	16-11-1978
5.	FCI (DCRG), (4th Amendment) Regulations, 1981.	-do-	25-7-1981
6.	FCI (DCRG), (5th Amendment) Regulations, 1982.	-do-	28-8-1982
7.	FCI (DCRG), (6th Amendment) Regulations, 1982.	-do-	2-10-1982
8.	FCI (DCRG), (7th Amendment) Regulations, 1983.	-do-	5-11-1983
9.	FCI (DCRG), (8th Amendment) Regulations, 1986.	-do-	14-10-1986
10.	FCI (DCRG), (9th Amendment) Regulations, 1986.	-do-	31-10-1986
11.	FCI (DCRG), (10th Amendment) Regulations, 1988.	-do-	19-4-1988
12.	FCI (DCRG), (1st Amendment) Regulations, 1990.	-do-	19-4-1990
13.	FCI (DCRG), (2nd Amendment) Regulations, 1990.	-do-	19-4-1990
14.	FCI (DCRG), (1st Amendment) Regulations, 1991.	-do-	09-8-1991

